



NEERAJ®

समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत-I

(Principles of Microeconomics-I)

B.E.C.C.-133

**Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers**

Based on

C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Syllabus of

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: Vaishali Gupta



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com

Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Content

समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत-I (Principles of Microeconomics-I)

Question Paper—June-2023 (Solved).....	1-2
Question Paper—December-2022 (Solved)	1-2
Question Paper—Exam Held in July-2022 (Solved).....	1-3

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
--------------	-----------------------------------	-------------

खण्ड-1 समष्टि अर्थशास्त्र में चर्चित विषय और राष्ट्रीय आय लेखा (Issues in Macroeconomics and National Income Accounting)

1. मुद्दे एवं संकल्पनाएँ	1
(Issues and Concepts)	
2. राष्ट्रीय आय लेखांकन.....	17
(National Income Accounting)	
3. आर्थिक निष्पादन के माप.....	33
(Measuring Economic Performance)	

खण्ड-2 सकल घरेलू उत्पाद का निर्धारण (Determination of GDP)

4. पारम्परिक और केनेसियन सिद्धांत.....	49
(Classical and Keynesian Systems)	
5. आय निर्धारण का केनेसियन प्रतिमान.....	66
(Keynesian Model of Income Determination)	

**खण्ड-3 खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का निर्धारण
(National Income Determination in an Open Economy with Government)**

- | | |
|---|----|
| 6. केनेसियन प्रतिमान में राजकोषीय नीति..... | 78 |
| (Fiscal Policy in Keynesian Model) | |
| 7. बाह्य क्षेत्र..... | 93 |
| (External Sector) | |

**खण्ड-4 आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा
(Money in a Modern Economy)**

- | | |
|-------------------------|-----|
| 8. मुद्रा के कार्य..... | 105 |
| (Functions of Money) | |
| 9. मुद्रा की माँग..... | 119 |
| (Demand for Money) | |
| 10. मौद्रिक नीति..... | 134 |
| (Monetary Policy) | |



**Sample Preview
of the
Solved
Sample Question
Papers**

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2023

(Solved)

समिष्ट अर्थशास्त्र के सिद्धान्त-I
(Principles of Macroeconomics-I)

B.E.C.C.-133

समय : 3 घण्टे]

[अधिकतम अंक : 100

नोट : सभी भागों के प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए।

भाग-क

नोट : इस भाग में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 1. एक अर्थव्यवस्था में आय और उत्पादन के चक्रीय प्रवाह को समझाइए। व्यवस्था से वापसियाँ (क्षरण) क्या हैं?

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-2, पृष्ठ-17, 'आय का प्रवाह'

प्रश्न 2. राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। व्यय विधि द्वारा हम राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार करते हैं?

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-2, पृष्ठ-24, प्रश्न 7 तथा अध्याय-3, पृष्ठ-33, 'व्यय विधि'

प्रश्न 3. क्लासिकल (परंपरागत) प्रणाली में उत्पादन और रोजगार का निर्धारण कैसे होता है? चित्र की सहायता से समझाइए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-4, पृष्ठ-50, 'पारंपरिक सिद्धांत में उत्पादन और रोजगार'

प्रश्न 4. मुद्रा के कार्य क्या हैं? मुद्रा पूर्ति के मापों का वर्णन कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-8, पृष्ठ-105, 'मुद्रा के कार्य', पृष्ठ-110, प्रश्न 3

भाग-ख

नोट : इस भाग में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 5. मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के फिशर दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-9, पृष्ठ-119, 'मुद्रा का परिमाण सिद्धांत : फिशर का दृष्टिकोण'

प्रश्न 6. भारत में मौद्रिक नीति के विभिन्न उपकरणों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-10, पृष्ठ-135, 'मौद्रिक नीति के साधन'

प्रश्न 7. उपयुक्त आरेख का प्रयोग करके केनेसियन क्रॉस की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-5, पृष्ठ-71, प्रश्न 5

प्रश्न 8. एक आरेख की सहायता से कर दरों में परिवर्तन का सन्तुलन उत्पाद पर प्रभाव समझाइए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-6, पृष्ठ-80, 'सरकारी खर्च और कर दर में परिवर्तन का प्रभाव'

प्रश्न 9. शुद्ध निर्यात (निवल निर्यात) से क्या अभिप्राय है? समझाइए कि विनिमय दर में परिवर्तन शुद्ध निर्यात को कैसे प्रभावित करता है।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-7, पृष्ठ-98, प्रश्न 6 तथा पृष्ठ-99, प्रश्न 7

प्रश्न 10. बैंकिंग प्रणाली द्वारा साख-सृजन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-8, पृष्ठ-107, 'बैंकिंग प्रणाली द्वारा साख सृजन'

प्रश्न 11. मात्रात्मक मुक्ति (मात्रात्मक सहजता) की अवधारणा और मुद्रा पूर्ति पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-10, पृष्ठ-139, 'परिमाणात्मक सहजता'

भाग-ग

प्रश्न 12. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट लिखिए-

(क) तरलता जाल

उत्तर-तरलता जाल एक प्रतिकूल आर्थिक स्थिति है, जो तब उत्पन्न हो सकती है, जब उपभोक्ता और निवेशक ब्याज दरें कम होने पर भी इसे खर्च करने या निवेश करने के बजाय नकदी जमा करते हैं, जिससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक नीति निर्माताओं के प्रयास बाधित होते हैं।

इस शब्द का प्रयोग पहली बार अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स द्वारा किया गया था, जिन्होंने तरलता जाल को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया था, जो तब हो सकती है, जब ब्याज दरें इतनी कम हो जाती हैं कि ज्यादातर लोग बांड और अन्य ऋण उपकरणों में पैसा लगाने के बजाय नकदी रखना पसंद करते हैं।

केन्स ने कहा, इसका प्रभाव मौद्रिक नीति निर्माताओं को धन की आपूर्ति बढ़ाकर या ब्याज दर को और कम करके विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शक्तिहीन बनाना है।

जब उपभोक्ता और निवेशक अपनी नकदी चेकिंग और बचत खातों में रखते हैं तो तरलता जाल विकसित हो सकता है, क्योंकि उनका मानना है कि ब्याज दरें जल्द ही बढ़ेंगी। इससे बांड की कीमतें गिर जाएंगी और वे कम आकर्षक विकल्प बन जाएंगे।

केन्स के समय से, तरलता जाल शब्द का उपयोग आने वाली किसी नकारात्मक घटना के बारे में चिंता के कारण बड़े पैमाने पर नकदी जमाखोरी के कारण होने वाली धीमी आर्थिक वृद्धि की स्थिति का वर्णन करने के लिए अधिक व्यापक रूप से किया गया है।

(ख) उच्च-शक्ति मुद्रा

उत्तर-वर्तमान प्रथा मौद्रिक आपूर्ति के निर्धारक को मौद्रिक आधार या उच्च शक्ति वाली मुद्रा के संदर्भ में समझाना है। उच्च शक्ति वाली मुद्रा वाणिज्यिक बैंक भंडार और जनता द्वारा रखी गई मुद्रा (नोट और सिक्के) का योग है। उच्च शक्ति वाली मुद्रा बैंक जमा के विस्तार और मुद्रा आपूर्ति के निर्माण का आधार है। इस प्रकार, उच्च शक्ति वाली मुद्रा की आपूर्ति सीधे मौद्रिक आधार में परिवर्तन के साथ और मुद्रा और आरक्षित अनुपात के विपरीत भिन्न होती है। उच्च शक्ति वाले धन के उपयोग में वाणिज्यिक बैंकों की कानूनी सीमा या केंद्रीय बैंक के पास आवश्यक भंडार और अतिरिक्त भंडार की मांग और मुद्रा के लिए जनता की मांग शामिल होती है। $50 + H = C + RR + ER$ जहां, C मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है RR = आवश्यक भंडार ER = अतिरिक्त भंडार एक वाणिज्यिक बैंक का भंडार उसकी जमा

राशि पर निर्भर करता है। लेकिन एक बैंक आमतौर पर अपनी आवश्यक आरक्षित निधि से अधिक आरक्षित निधि रखता है। दरअसल, बैंक कानूनी सीमा से ठीक कम तक ऋण नहीं देते हैं। इसलिए उनके द्वारा अतिरिक्त भंडार बनाए रखने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इस प्रकार, मुद्रा आपूर्ति आवश्यक आरक्षित अनुपात और वाणिज्यिक बैंक के अतिरिक्त आरक्षित अनुपात द्वारा निर्धारित होती है। आवश्यक आरक्षित अनुपात (RRR) जमा करने के लिए आवश्यक भंडार का अनुपात है (RR/D) और अतिरिक्त आरक्षित अनुपात (ERR) जमा करने के लिए अनुपात या अतिरिक्त भंडार है (ER/D)। जनता द्वारा मुद्रा की मांग को बैंक जमा के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा अनुपात $C_r = C/D$ हैं जहां C मुद्रा है और D जमा है। मुद्रा अनुपात ऐसे कारकों से प्रभावित होता है, जैसे लोगों की आय के स्तर में बदलाव, जनता द्वारा क्रेडिट उपकरणों का उपयोग और आर्थिक गतिविधि में अनिश्चितताएं।

मुद्रा आपूर्ति और उच्च शक्ति वाली मुद्रा के बीच औपचारिक संबंध को समीकरणों के रूप में बताया जा सकता है-धन आपूर्ति (M) में वाणिज्यिक बैंक (D) और जनता द्वारा रखी गई मुद्रा (C) की जमा राशि शामिल है। इस प्रकार धन की आपूर्ति, $M = D + C - (1)$ उच्च शक्ति वाले धन (H) (या मौद्रिक आधार) में जनता द्वारा रखी गई मुद्रा शामिल है (C) आवश्यक भंडार (RR) और वाणिज्यिक बैंकों के अतिरिक्त भंडार रखता है।

(ग) व्यापार शेष

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-7, पृष्ठ-93, 'व्यापार संतुलन'

(घ) अदृश्य हाथ

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-4, पृष्ठ-49, 'अदृश्य हाथ'

Sample Preview of The Chapter

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धान्त-I

(Principles of Macroeconomic-I)

मुद्दे एवं संकल्पनाएँ (Issues and Concepts)

1

परिचय

सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जो घरों और फर्मों जैसे आर्थिक एजेंटों से संबंधित मुद्दों से संबंधित है। घरों के मामले में, हम बजट की कमी के अधीन उपयोगिता अधिकतमीकरण के मुद्दे से निपटते हैं। इसी तरह, फर्मों के मामले में, हम संसाधन की कमी के अधीन लाभ अधिकतमीकरण (या इसके विपरीत लागत न्यूनतमीकरण) के मुद्दे से निपटते हैं। ऐसे मुद्दे एक घर द्वारा उपयोगिता को अधिकतम करने और न्यूनतम करने से संबंधित हैं—

किसी फर्म द्वारा लागत (या लाभ को अधिकतम करना) सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विषय है। विभिन्न रेखाचित्रों के माध्यम से हमने सीखा कि परिवार किन बाधाओं का सामना करते हैं और वे उपभोग के अपने इष्टतम स्तर तक कैसे पहुँचते हैं और किस प्रकार साधनों का चुनाव करते हैं। फर्मों के व्यवहार के विश्लेषण के लिए एक समान उपचार किया जाता है, जहाँ कंपनियां अपने लिए उपलब्ध इनपुट और संसाधनों की कीमतों को देखते हुए अपने उत्पादन स्तर को अनुकूलित करती हैं। यही अनुकूलन समस्या देशों पर भी लागू होती है। देशों के भी कुछ वस्तुनिष्ठ कार्य होते हैं और उन्हें बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। किसी देश के लिए उद्देश्य कार्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि को अधिकतम करना, परिवारों के बीच गरीबी को कम करना, स्थिर मूल्य स्तर बनाए रखना, व्यक्तियों के बीच आय के वितरण में असमानता को कम करना आदि हो सकता है। इन मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए व्यापक अर्थशास्त्र की सहायता ली जाती है।

मैक्रोइकॉनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वह शाखा है, जो समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के व्यवहार का अध्ययन करती है। इस प्रकार यह राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय निवेश, निर्यात, आयात आदि जैसे समग्र चरों से संबंधित है।

अध्याय का विहंगावलोकन

समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करें?

बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में, समष्टि अर्थशास्त्र जैसा कोई अर्थशास्त्र नहीं था। कुगमैन और वेल्स के अनुसार, रैग्नर फ्रिश द्वारा मैक्रोइकॉनॉमिक्स शब्द की रचना 1933 में की गई थी, जिसका सैद्धांतिक विकास 1936 में जेएम केन्स की पुस्तक 'जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी' के प्रकाशन के साथ हुआ।

जैसा कि हम जानते हैं, मैक्रोइकॉनॉमिक्स एक अर्थव्यवस्था में समग्र व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र की एक विशेष शाखा की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न होती है, क्योंकि व्यक्तिगत इकाइयों के लिए जो बात लागू होती है, वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी लागू हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई कंपनी उत्पादन (जैसे सीमेंट) के उत्पादन के लिए श्रमिकों को नियुक्त करती है। यह चालू वेतन दर पर जितने श्रमिकों की आवश्यकता हो, उतने श्रमिकों को काम पर रख सकती है। इस प्रकार किसी एक फर्म द्वारा श्रम की मांग में वृद्धि का मजदूरी दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि, यदि सभी कंपनियाँ श्रम की माँग बढ़ाती हैं (जैसे कि देश में आर्थिक उछाल और आशावाद के कारण), तो श्रम की कमी होगी और मजदूरी दर में वृद्धि

होगी। इसके अलावा, देश में काम के लिए उपलब्ध श्रमिकों की संख्या सीमित है। इस प्रकार इस सीमा से अधिक श्रम की मांग से केवल मजदूरी दर में वृद्धि होगी, श्रम की आपूर्ति में नहीं।

इसे एक अन्य उदाहरण से समझते हैं, जैसे किसी परिवार द्वारा की गई बचत उसके देश की कुल बचत होगी। वस्तुतः यदि कोई व्यक्ति अधिक पैसा बचाएगी तो उसे अपनी बचत पर ब्याज भी प्राप्त होगा और उसकी आय के स्तर में वृद्धि होगी। इस तथ्य का एक अन्य पहलू भी है, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाता है तो उसका उपभोग व्यय उसी मात्रा में काम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वस्तु और सेवाओं के लिए उसकी मांग कम हो जाएगी। परिणामस्वरूप, व्यापारी की आय (मुनाफा) कम हो जाती है। यदि व्यापारी की आय कम हो जाती है, तो व्यापारी ने वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर जितना पैसा खर्च किया होगा, वह कम हो जाता है और यह सिलसिला निरंतर चलता रहता है।

हालांकि, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम उपभोग करते हैं, तो हम वस्तुओं और सेवाओं की मांग उत्पन्न करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं की ऐसी मांग से देश में उत्पादन गतिविधियों और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है। यदि वस्तुओं और सेवाओं की मांग नहीं होगी तो देश में कोई उत्पादन नहीं होगा, कोई रोजगार नहीं होगा और कोई आय सृजन नहीं होगा। इस प्रकार, यह देश के हित में है कि घरेलू खपत में लगातार वृद्धि हो। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रायः यह कहा जाता है कि बचत एक निजी गुण है, लेकिन एक सामाजिक बुराई है, इस समस्या को मितव्ययिता का विरोधाभास कहा जाता है।

अक्सर व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर को पेड़ों और जंगल का उदाहरण देकर समझाया जाता है। जंगल में विभिन्न प्रकार के पेड़ होते हैं और हर एक अलग हो सकता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र जंगल में पेड़ों, उनकी प्रजातियों, आयामों, वृद्धि, आयु आदि का अध्ययन करने जैसा है। समष्टि अर्थशास्त्र जंगल का अध्ययन करने जैसा है। इसका क्षेत्र, घनत्व, संरचना और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र। हम पेड़ों के लिए जंगल को नजरंदाज नहीं कर सकते-स्थूल पहलू जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही सूक्ष्म पहलू भी। जबकि सूक्ष्म अर्थशास्त्र फर्मों और परिवारों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए उपयोगी है, वहीं व्यापक अर्थशास्त्र नीति निर्माण और नीति मूल्यांकन में सहायक है।

कुछ संकल्पनाएँ

स्टॉक और प्रवाह

किसी भी स्टॉक का मापन किसी एक समयबिंदु पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी देश के पूँजी भंडार में मशीनें, उपकरण और इमारतें शामिल हैं। यह राष्ट्र की पुनरुत्पादित संपदा होती है अर्थात् इसमें वे संसाधन शामिल हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में मदद करते हैं। पूँजी का स्टॉक किसी विशेष तिथि पर मापा जा सकता है। धन आपूर्ति, श्रम बल और बाह्य ऋण स्टॉक के कुछ अन्य उदाहरण हैं।

प्रवाह को समय के अंतराल पर मापा जाता है; इस प्रकार यह एक दर है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किसी फर्म का उत्पादन प्रतिदिन या प्रतिमाह के आधार पर मापा जा सकता है। अन्यथा, समय आयाम के बिना उत्पादन अस्पष्ट है। इसी तरह, यदि यह कहा जाए कि मेरी आय रु. 10,000, यह अस्पष्ट है - क्या यह एक दिन के लिए है, एक सप्ताह के लिए है या एक महीने के लिए है? समष्टि अर्थशास्त्र का आधार यही तर्क होता है। उदाहरण के लिए, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक प्रवाह है। यह एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। आय, व्यय, बचत, निवेश, उपभोग, लाभ, उधार आदि प्रवाह के उदाहरण हैं। स्टॉक में परिवर्तन के माध्यम से समय के साथ स्टॉक जमा होता जाता है। गणितीय रूप से, स्टॉक को समय की अवधि में प्रवाह चर के एकीकरण के रूप में देखा जा सकता है।

अल्पावधि और दीर्घावधि

अल्पावधि में उत्पादन के कुछ कारक निश्चित हो जाते हैं। किसी भी फर्म के लिए दृढ़ पूँजी और प्रौद्योगिकी को अल्पावधि में स्थिर माना जाता है; दीर्घावधि के अंतर्गत ही इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार लंबे समय में, इसके लिए कोई बाधा नहीं है और जब उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं तो फर्म अपने उत्पादन को अधिकतम कर सकती है।

समष्टि अर्थशास्त्र में अल्पावधि और दीर्घावधि शब्दों का उपयोग व्यष्टि अर्थशास्त्र से कुछ अलग है। समष्टि अर्थशास्त्र में, हम कुछ चरों को अल्पावधि में अनम्य मानते हैं, विशेष रूप से मूल्य स्तर और मजदूरी दर। परंपरागत अर्थशास्त्रियों ने इस अर्थ में कीमत और वेतन दरों को पूरी तरह से सुनम्य माना अर्थात् वे तात्कालिक रूप से कुल मांग और कुल आपूर्ति में परिवर्तनों के आधार पर समायोजित हो जाती हैं। केन्स के अनुसार ये चर सुनम्य हैं और उन्हें अपने वांछित स्तर पर समायोजित होने के लिए समय की आवश्यकता होती है। इस

प्रकार कीमतें और मजदूरी दीर्घावधि में अपने संतुलन स्तर तक पहुँचती हैं, अल्पावधि में नहीं।

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पूँजी निवेश के प्रवाह में समय लगता है, यह दीर्घावधि में होता है, अल्पावधि में नहीं। विभिन्न देशों में पूँजी की आवाजाही एक अन्य चर है, जो लंबे समय में इसके संतुलन स्तर पर समायोजित हो जाती है। ऐसे प्रवाह का प्रभाव एक निश्चित अवधि तक फैलता है।

आर्थिक प्रतिमान

अर्थशास्त्र में प्रायः 'मॉडल' या प्रतिमान शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह वास्तविकता के सरलीकृत संस्करण को संदर्भित करता है। यह आर्थिक व्यवहार को समझने, विश्लेषण करने और पूर्व अनुमान लगाने में सहायक होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में, यह समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। व्यापक आर्थिक मॉडल में हम प्रासंगिक व्यापक आर्थिक चर (जैसे—आय, उत्पादन, व्यय, निवेश, बचत, निर्यात आदि) की पहचान करते हैं और उनके बीच संबंध स्थापित करते हैं। इन चरों के बीच संबंधों को आरेखों या गणितीय समीकरणों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। एक आर्थिक मॉडल कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है। ये धारणाएँ आवश्यक हैं, ताकि सूक्ष्म विवरणों को नजरंदाज कर दिया जाए और आवश्यक तत्वों को शामिल किया जाए। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। किसी फर्म में, हम मानते हैं कि उत्पादन के दो कारक हैं अर्थात् पूँजी और श्रम। हम सभी प्रकार के श्रम को एक सजातीय श्रेणी में रखते हैं। हम क्षेत्र में एक प्रबंधक और एक कार्यकर्ता के बीच अंतर को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार, उदासीनता वक्र का वर्णन करते समय हम घरों के प्रकार को नजरंदाज कर देते हैं। एक अमीर घर का व्यवहार एक गरीब घर के व्यवहार से भिन्न होगा या ग्रामीण क्षेत्र के परिवार का व्यवहार शहरी क्षेत्र के परिवार से भिन्न होगा। ऐसे विवरणों को नजरंदाज किया जाता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य घरों के व्यवहार से लेकर कीमतों और आय में बदलाव का विश्लेषण करना है।

केनेसियन मॉडल में, मैक्रोइकॉनॉमिक्स से एक उदाहरण लेने के लिए, कुल खपत, कुल निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात जैसे समग्र चर पर विचार किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादन का संतुलन स्तर निर्धारित किया जाता है। घरों और फर्मों के व्यवहार को नजरंदाज करते हैं।

कई विकास मॉडल (जैसे कि हैरोड-डोमर मॉडल या सोलो मॉडल) मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक क्षेत्र शामिल है, एक समग्र उत्पादन फलन है, जो समग्र उत्पादन (यानी कुल

उत्पादन) और समग्र आदनों (यानी कुल पूँजी और कुल श्रम) के बीच संबंध दर्शाता है। यह अवास्तविक लग सकता है, लेकिन इन विकास मॉडलों का उद्देश्य आर्थिक विकास, बचत अनुपात और जनसंख्या वृद्धि के लिए संतुलन स्थितियों का विश्लेषण करना है। ये मॉडल विवरणों को नजरंदाज करते हैं, लेकिन निकाले गए व्यापक निष्कर्ष नीति निर्माण में सहायक होते हैं।

वृद्धि दर

हम अपने दैनिक व्यवहार में अक्सर विकास दर का उपयोग करते हैं। व्यक्ति उस दर से चिंतित होता है, जिस दर से उसका वेतन पूरे वर्ष में बढ़ा, उसकी बचत पर उसे मिलने वाली ब्याज की दर और मुद्रास्फीति की दर जो उसकी क्रय शक्ति को प्रभावित करती है। व्यापक स्तर पर किसी व्यक्ति की दिलचस्पी इस बात में हो सकती है कि भारत की जनसंख्या किस दर से बढ़ रही है या जीडीपी बढ़ रही है। उपर्युक्त सभी मामलों में विकास दर की गणना समान है। किसी चर की वार्षिक वृद्धि दर की गणना इस प्रकार की जाती है—

$$\text{वृद्धि दर} = \frac{\text{चालू वर्ष में मान} - \text{पिछले वर्ष में मान}}{\text{पिछले वर्ष में मान}} \times 100$$

$$\text{वृद्धि दर} = \frac{\text{चालू वर्ष की सकल घरेलू उत्पाद} - \text{पिछले वर्ष की सकल घरेलू उत्पाद}}{\text{पिछले वर्ष की सकल घरेलू उत्पाद}} \times 100$$

हमने पाया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत की जीडीपी मौजूदा कीमतों पर 190.10 लाख करोड़ रुपए थी, जबकि 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर 170.95 लाख करोड़ रुपए थी। यदि हम इन मानों को उपर्युक्त समीकरण में रखते हैं तो हमें 11.20 प्रतिशत प्राप्त होता है। इस प्रकार हम जीडीपी की विकास दर की गणना करते हैं। 2018-19 के लिए 170.95 से ऊपर 11.20 प्रतिशत है! जैसा कि हम आधिकारिक आंकड़ों और समाचार पत्रों की रिपोर्टों से देखते हैं, 2018-19 के दौरान भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर इतनी अधिक नहीं है; यह बहुत कम है। हम जो गलती करते हैं, वह यह है कि हम मौजूदा कीमतों पर जीडीपी पर विचार करते हैं, जिसमें उत्पादन में वृद्धि और कीमतों में वृद्धि शामिल होती है। हालांकि, हमारा उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान उत्पादन में वृद्धि का अनुमान प्राप्त करना है। हमें मूल्य वृद्धि के प्रभाव को बेअसर करने की आवश्यकता है, इसके लिए हम स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद पर विचार करते हैं।

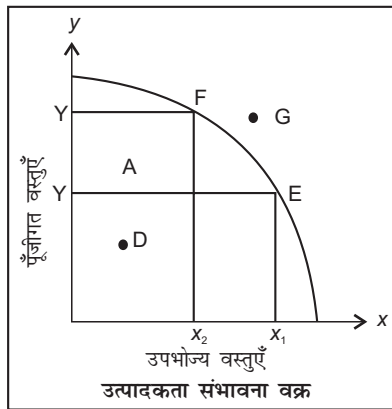
उत्पादन संभाव्यता वक्र

उच्च आर्थिक विकास प्राप्त करना अधिकांश देशों की आर्थिक नीति के उद्देश्यों में से एक है, हालांकि किसी देश

की आर्थिक वृद्धि निश्चित सीमा से अधिक नहीं हो सकती है। यह सीमा निर्भर करती है—भूमि, श्रम, पूँजी, कच्चा माल, ऊर्जा और तकनीकी जानकारी जैसे आदानों की उपलब्धता पर। कुछ संसाधनों की उपलब्धता भी सीमित है, जैसे यदि किसी देश में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं तो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की आपूर्ति कम हो सकती है। हर साल सरकार बजट प्रस्तुत करती है, जिससे हमें सरकार की नीति और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सूचना मिलती है तथा पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा।

यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यय की विभिन्न मदों पर आवंटित संसाधन सीमित हैं। सामान्यतः किसी देश के सामने कई बाधाएँ होती हैं—गतिविधियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट नहीं हो सकता है, कुछ रणनीतिक कच्चे माल की आपूर्ति में कमी हो सकती है, किसी परियोजना की शुरुआत के बीच एक लंबी अवधि हो सकती है और उसका पूरा होना, इत्यादि। समष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन संभाव्यता वक्र के माध्यम से किसी देश के समक्ष आने वाली रुकावटों को दर्शाया जाता है। उत्पादन संभाव्यता वक्र (पीपीसी) किसी देश की संभावित जीडीपी को दर्शाता है। देश में वास्तव में जो उत्पादन हो रहा है, वह भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब उत्पादन पीपीसी पर होता है (चित्र में बिंदु ई और एफ देखें), तो सभी संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। यदि उत्पादन पीपीसी के अंदर किसी बिंदु पर होता है (बिंदु ए और डी देखें), तो कुछ संसाधनों का कम उपयोग होता है। पीपीसी के बाहर एक बिंदु, जैसे चित्र में जी, प्राप्य नहीं है। यदि देश पीपीसी के अंदर एक बिंदु पर काम कर रहा है, तो नीचे दिए गए अनुसार 'आउटपुट अंतराल' है।

आउटपुट अंतराल = संभावित आउटपुट – वास्तविक आउटपुट



संभावित सकल घरेलू उत्पाद दो तरीकों से समय के साथ बढ़ सकता है—तकनीकी प्रगति और अधिक संसाधनों का संचय। ऐसे मामलों में पीपीसी बाहर की ओर दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। यदि पीपीसी पर्याप्त रूप से बाहर की ओर स्थानांतरित हो जाता है, तो बिंदु जी (जो पहले प्राप्य नहीं था) प्राप्त किया जा सकता है। जब किसी देश का पीपीसी बाहर की ओर स्थानांतरित होता है, तो देश में आर्थिक विकास होता है।

आर्थिक संवृद्धि का महत्त्व

किसी अर्थव्यवस्था की विकास दर उसके वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से आंकी जाती है। अधिकांश देशों के उद्देश्यों में विकास दर को अधिकतम करना होता है। हम देखते हैं कि विभिन्न देशों में विकास दर अलग-अलग होती है। उदाहरण के तौर पर, चीन जैसे देशों में दशकों से प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर देखी गई है, वहीं कई अफ्रीकी देश भी हैं, जहां विकास नगण्य रहा है।

विश्व युद्ध के बाद की अवधि में जापान की अत्यधिक उच्च आर्थिक वृद्धि को एक चमत्कार माना जाता है। हालांकि, पिछले 20 वर्षों में, जापान में गंभीर आर्थिक संकट रहा है। अर्जेंटीना, एक लैटिन अमेरिकी देश, बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस जैसे कई देशों से अधिक समृद्ध था। अर्जेंटीना विशाल प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, खासकर कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में। 1913 में अर्जेंटीना की प्रति व्यक्ति आय 3797 डॉलर थी, जबकि फ्रांस की 3452 डॉलर और जर्मनी की 3134 डॉलर थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, 2019 में अर्जेंटीना की प्रति व्यक्ति आय 9887 डॉलर है, जबकि फ्रांस और जर्मनी का क्रमशः 41760 डॉलर और 46563 डॉलर है। यह दर्शाता है कि पिछली शताब्दी में फ्रांस और जर्मनी की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि अर्जेंटीना की तुलना में बहुत तेजी से हुई है। अर्जेंटीना की विकास दर में इस सापेक्ष स्थिरता के लिए अर्थशास्त्रियों ने राजनीतिक अस्थिरता, तकनीकी प्रगति की कमी, आयात-प्रतिस्थापन (निर्यात प्रोत्साहन के बजाय) की विकास रणनीति का पालन और उच्च मुद्रास्फीति सहित कई कारकों को जिम्मेदार माना है। दूसरे उदाहरण में, चीन और भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं, जो कि विश्व की दो प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएँ हैं। 1990 तक भारत और चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग समान स्तर पर थी। हालांकि, बाद के समय में चीन की विकास दर भारत की तुलना में बहुत अधिक थी। 2018 में, भारत की प्रति